एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में प्रतिगामी और असंवैधानिक परिवर्तन पर एआईपीएसएन का विरोध

नोट

नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा सामग्री में परिवर्तन 2020पर अखिल भारतीय जन विज्ञान नेटवर्क (एआईपीएसएन)ने चिंता व्यक्त की है। संगठन को एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में प्रस्तावित परिवर्तनों से व्यापक स्तर पर शैक्षिणिकराजनीतिक और सामाजिक प्रभाव की आशंका है ,शैक्षिक ,। यह परिवर्तनों अकादमिक स्तर के विचारवितर्क के बिना किए गए हैं-विमर्श या तर्क-। स्कूली स्तर पर उपयोग की जाने वाली सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में संशोधन करने से पूर्व एससीईआरटी स्कूल शिक्षकों और ,राज्य शिक्षा विभाग ,विशाल अकादमिक समुदाय से कोई परामर्श नहीं किया गया। सभी परिवर्तन काफी जल्दबाज़ी में किए गए हैं। क्योंकि सरकारों के पास नीति निर्माण और निर्णय लेने की शक्ति है इसलिए शिक्षाविदोंशिक्षकों और जन विज्ञान , (एनईपी) आंदोलनों ने पहले भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, के बारे में 2020अपनी शंकाओं को केंद्र और राज्य सरकारों के समक्ष स्पष्ट किया है।

इस सम्बंध में इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हाल ही में की गई जांच से पता चला है कि एनसीईआरटी ने करोड़ों छात्रों को शामिल करते हुए स्कूल में उपयोग की जाने वाली सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में सबसे अपारदर्शी तरीके से परिवर्तन किए हैं। क्योंकि एनसीईआरटी भारत सरकार का एक विशिष्ट शीर्ष संस्थान है इसलिए इस प्रकिया में राज्य स्तर पर कार्यरत अधिकारियों और शिक्षाविदों को शामिल किया जाना चाहिए था। एनसीईआरटी की पहुंच बहुत व्यापक है और यह किसी विशेष राज्य तक सीमित नहीं है। क्योंकि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्कूली स्तर पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में उपयोग की जाने वाली पाठ्यपुस्तकें समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं इसलिए इस प्रक्रिया में शैक्षिणिक आवश्यकताओं और भारतीय संविधान में निहित स्कूल शिक्षा सम्बंधी प्रावधानों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनाया जाना चाहिए था।

इन संशोधनों में राज्यधर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान में निहित शिक्षा ,लोकतंत्र का उद्देश्य ,नागरिक सम्बंध- के संवैधानिक उद्देश्य से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओंपर हस्तक्षेप किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की जांच रिपोर्ट के अनुसार यह संशोधन गैरपारदर्शी तरीके से किए गए हैं-। कई हिस्सों को हटाना उनका संशोधन , सामाजिक विज्ञान की किताब को दोबारा लिखने जैसा है। सामाजिक विज्ञान की संशोधित पाठ्यपुस्तक में 2002 के दौरान गुजरात में मुसलमानों के विरुद्ध हिंसा और 1975-में आपातकाल से सम्बंधित सामग्री भी शामिल 77 है। एनसीईआरटी ने इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में रानीतिक और वैचारिक रूप से प्रेरित परिवर्तनों को शामिल करने का सुझाव दिया है। इसमें दिल्ली सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य से सम्बंधित सामग्री को हटाना शामिल है। यह संशोधन स्कूली छात्रों में जाति व्यवस्था की असमानताओं और नर्मदा बचाओं आंदोलन जैसे सामाजिक आंदोलनों की समझ को भी प्रभावित करेंगे।

इन परिवर्तनों से यह स्पष्ट है कि स्कूल में पढ़ाई जाने वाली पाठ्यपुस्तकों को फिर से लिखा जा रहा है। यह पुनर्लेखन की प्रक्रिय्या एक प्रतिगामी राजनीति और विचारधारा को बढ़ावा देने से प्रेरित है। इसका उद्देश्य अत्यधिक संदिग्ध और दमनकारी प्रक्रिया के माध्यम से समाज के भीतर गंभीर चिंतन को पूरी तरह से खत्म करना है। स्कूली शिक्षा की पाठ्यपुस्तकों में सुझाय गए परिवर्तन इसी विचार को परिलक्षित करते हैं। वह नहीं चाहते कि छात्र जाति व्यवस्था में हो रहे अन्याय के बारे में सीखें। पाठ्यक्रमों में इस तरह के परिवर्तन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की स्थापना होगी जिसमें छात्रों को जातिनौ-वर्ग और राजनीतिक ,समुदाय ,करशाही तंत्र जैसे संस्थानों के वास्तविक कामकाज और भारत में सामाजिक विरोध के वास्तविक कारणों को समझने से रोका जाएगा।

पिछली सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों का संपादन करने वाले सामाजिक वैज्ञानिकों और अकादमिक समुदाय को शामिल किए बिना वर्तमान सामाजिक डोमेन में परिवर्तन उन लोगों द्वारा किए जा रहे हैं जिनका सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है। एनसीआरटी की इस प्रक्रिया में शिक्षा मंत्रालय का पूर्ण समर्थन रहा है। यह परिवर्तन वास्तव में हिंदुत्व के एजेंडे को दर्शाते हैं जो स्कूली शिक्षा के माध्यम से अनुदार राजनीतिक-नौकरशाही, अकादमिक तंत्र और समाज का निर्माण करना चाहते हैं। एक सांप्रदायिक रूप से चार्जड समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें नागरिकों द्वारा विरोध को सामाजिक विपथन के रूप में देखा जाए और हर तरह से अस्वीकार किया जाए।

पूर्व में पीएसएम ने 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण और घोषण के दौरान यह आशंका जताई थी कि शिक्षा में अपेक्षित बदलाव प्रतिगामी होंगे लेकिन शिक्षा में हालिया परिवर्तन और अधिक खतरनाक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। सत्ताधारी दल के नेतृत्व वाली राज्य सरकारें विभिन्न राज्यों में सक्रीय रूप से यही प्रक्रिया अपना रही हैं। कर्नाटक सरकार भी इसी तरह के बदलाव करने के लिए कटिबद्ध है। राज्य स्तर पर विपक्षी दलों और सामाजिक आंदोलनों के विरोध के बावजूद सरकार इन बदलावों के साथ आगे बढ़ रही है। इसका मतलब स्पष्ट है कि सत्ताधारी दल को संवैधानिक दायित्वों का पालन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।

रानीतिक-नौकरशाही तंत्र ऐसे परिवर्तनों के लिए एनसीईआरटी का उपयोग कर रहा है जो राज्य और लोकतंत्र, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। जन विज्ञान आंदोलन केंद्र सरकार से गैर-शैक्षिणिक और सांप्रदायिक उद्देश्य से पाठ्यपुस्तकों में इस प्रकार के तर्कहीन परिवर्तनों को रोकने का आग्राह करता है। मौजूदा पाठ्यपुस्तकों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने से पहले शिक्षाविदों के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा विकसित करना चाहिए जो हमारे संविधान और संवैधानिक मूल्यों के प्रात दृढ़ विश्वास और शिक्षाशास्त्र में गहरी समझ रखते हैं। पाठ्यपुस्तकों में कोई भी परिवर्तन अकादमिक तर्क और शैक्षिणिक समझ के साथ किया जाना चाहिए। जन विज्ञान आंदोलन जनता से अपील करता है कि वह सामने आएं और एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यपुस्तकों में जल्दबाज़ी, प्रतिगामी, असंवैधानिक और गैर-शैक्षिणिक परिवर्तनों का विरोध करें।

संभावित कार्य

1. इस विषय पर एक राष्ट्र स्तरीय ऑनलाइन बैठक का आयोजन
2. सभी राज्यों में प्रेस नोट का विमोचन
3. एनईपी के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य विशिष्ट कार्यों के प्रतिगामी उपायों पर प्रकाश डालने हेतु प्रेस कॉन्फ्रेंस
4. कस्बों में छोटे समूह में विरोध
5. मुद्दा आधारित समान मंच बनाने की संभावनाओं की तलाश और उस मंच के एक प्रमुख एजेंडे की तैयारी।
6. इसे लोकप्रिय एजेंडा के रूप में बदलने के लिए सेमिनार और चर्चाएं
7. सोशल मीडिया अभियान की संभावनाओं की तलाश
8. जनप्रतिनिधियों को पत्र
9. कोई अन्य संयुक्त कार्य जो जनता के ध्यान को आकर्षित करे
10. संबंधित राज्यों में एनईपी के कार्यान्वयन के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके की निगरानी के लिए प्रत्येक राज्य में एक छोटी टीम का गठन
11. वॉल राइटिंग, पोस्टर राइटिंग जैसे संभावनाओं की तलाश